लखनऊ, भोपाल, जयपुर, आगरा, गोण्डा, सुल्तानपुर, अमेठी और फैज़ाबाद में प्रसारित

हिन्दी व अंग्रेज़ी साप्ताहिक समाचारपत्र

खुशी समय

KHUSHI SAMAY

RNI No.: UPBIL/2012/46720

HINDI & ENGLISH WEEKLY NEWSPAPER

LUCKNOW

● वर्ष 9 ● अंक 18 | लखनऊ, रविवार 28 फरवरी 2021 | पृष्ठ - 8 मूल्य -2 रुपये

२५० रुपये में मिलेगी कोरोना वैक्सीन की एक खुराक, केंद्र सरकार ने तय की कीमत

नई दिल्ली (आईएनआईएस) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निजी अस्पताल कोविड-१६ टीके की प्रति खुराक के लिए २५० रुपये तक का शुल्क ले सकते हैं।

देश में एक मार्च से ६० वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित ४५ वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण करने की तैयारी चल रही है। मंत्रालय ने टीकाकरण में शामिल किए जाने वाले ४५ से ५६ वर्ष की आयु के लोगों में २० गंभीर बीमारियों के बारे में भी बताया। इनमें हृदय की बीमारी, कोरोनरी धमनी रोग, सीटी ए एमआरआई-स्ट्रोक, १० साल से अधिक समय से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी आदि शामिल हैं।

कोविड-१६ टीका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जायेगा जबकि निजी अस्पतालों में लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, ''टीके के लिए अधिकतम शुल्क २५० रुपये लिया जाएगा, जिसमें १५० रुपये टीके की कीमत और १०० रुपये सेवा शुल्क है। यह व्यवस्था अगले आदेशों तक लागू रहेगी।'' इन सभी सूचनाओं को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीकाकरण पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और मिशन निदेशकों (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के साथ बातचीत के दौरान साझा किया।

मंत्रालय ने कहा, ''आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत लगभग १०,००० निजी अस्पतालों, सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध ६०० से अधिक अस्पतालों और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत अन्य निजी अस्पताल कोविड टीकाकरण केन्द्रों (सीवीसी) के रूप में शामिल हो सकते हैं।'' मंत्रालय ने कहा, ''राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभागों ने पहले ही इन निजी अस्पतालों के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि उन्हें सीवीसी के रूप में इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।'' इन सभी निजी अस्पतालों की एक सूची स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि 'ऑन-साइट' पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी, ताकि योग्य लाभार्थी अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं और टीका लगवाएं। टीके के लाभार्थी को-विन २.० पोर्टल डाउनलोड कर और आरोग्य सेतु आदि मोबाइल ऐप के जरिए पहले भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

मंत्रालय ने कहा था कि लाभार्थी अपनी पसंद के कोविड-१६ टीकाकरण केंद्र (सीवीसी) को चुन सकते हैं और टीका लगवाने के लिए अपना समय निर्धारित करवा सकते हैं। कोविड-१६ के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान १६ जनवरी को शुरू हुआ था। मंत्रालय ने कहा था कि सभी लाभार्थियों को तस्वीर युक्त पहचान पत्र--आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र--आदि लेकर टीकाकरण केंद्र जाना होगा। वहद्र, किसी बीमारी से ग्रसित ४५ वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी को बीमारी से संबद्ध प्रमाणपत्र भी साथ लाना होगा, जिस पर पंजीकृत चिकित्सक के हस्ताक्षर होने चाहिए।

देश में शनिवार को लगातार तीसरे दिन कोविड-१६ के १६,००० से अधिक मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर १,१०,७६,६७६ हो गयी जबकि अब तक १,०७,६३,४५१ लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह आठ बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले २४ घंटे में कोरोना के १६,४८८ केस मिले जबकि ११३ और लोगों की मौत से मृतकों की कुल संख्या १,५६,६३८ हो गयी है। आंकड़ों के मुताबिक, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या १,५६,५६० है जो कि संक्रमण के कुल मामलों का १.४४ प्रतिशत है। संक्रमण से अब तक १,०७,६३,४५१ लोग स्वस्थ हो चुके हैं जिससे ठीक होने की दर ६७.१४ प्रतिशत हो गयी है जबकि मृत्यु दर १.४२ प्रतिशत है। देश में शुक्रवार को संक्रमण के १६,५७७ मामले और बृहस्पतिवार को १६,७३८ मामले आए थे। पिछले २४ घंटे में संक्रमण से ११३ और लोगों की मौत हो गयी। इनमें महाराष्ट्र से ४८, पंजाब से १५ और केरल से १४ लोगों की मौत के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक ५२,०४१, तमिलनाडु में १२,४८८ , कर्नाटक में १२,३२० , दिल्ली में १०,६०६, पश्चिम बंगाल में १०,२६३, उत्तर प्रदेश में ८,७२५, आंध्र प्रदेश में ७१६६ लोगों की मौत हुई है। लक्षद्वीप में कोरोना वाायरस संक्रमण से पहली मौत होने की खबर है।

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों को मिले १५ प्रतिशत आरक्षण

लखनऊ (एस.एन.लाल) केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास आठवले ने उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों को १५ प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है। महाराष्ट्र में दलितों के बड़े नेता आठवले शनिवार को लखनऊ में थे। उन्होंने कहा, 'किसी भी बिरादरी के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारा करते हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए।' उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए १५ फीसदी आरक्षण की मांग की। उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में कहा कि हमारी सरकार किसानों के खिलाफ नहद्र है, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि औषि कानूनों की वापसी की मांग ठीक नहद्र है क्योंकि अगर एक कानून वापस लिया गया तो आगे इसी तरह और भी मांगें होती रहेंगी।

आठवले ने किसान नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान नेता किसानों को तकलीफ दे रहे हैं। जातीय जनगणना की पैरवी करने के साथ ही आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में जाट और उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय आरक्षण मांग रहे हैं। सरकार से वह मांग कर रहे हैं कि इन सभी को १०-१५ फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। रिपब्लिकन पाटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के शनिवार के वाराणसी दौरे पर तीखी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर या कहद्र भी जाएं, कांग्रेस में राहुल गांधी के रहते उस पाटी का भला नहद्र हो सकता।

उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी से त्च् को यूपी में ५ से ६ सीटें देने की अपील की है। वहद्र, उन्हों ने जातिगत जनगणना करने की मांग करते हुए कहा कि इससे जातिवाद नहद्र बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान उनकी पाटी सभी राज्यों में चुनाव लड़ेगी। एनडीए सरकार में सहयोगी आरपीआई के अध्यक्ष ने कहा कि सभी जगह भारतीय जनता पाटी से सीटों को लेकर बात चल रही है। जहां भी सीटों पर समझौता नहद्र हो पाएगा, वहां हम एनडीए को समर्थन देंगे। उनका कहना था कि चार राज्यों में भाजपा की जीत लगभग तय है, केरल में भी भाजपा जीत सकती है।आठवले ने उत्तर प्रदेश में भीम आमी प्रमुख चंद्रशेखर की सक्रियता के सवाल पर कहा कि वह कोई खास प्रभाव डालने वाले नहद्र हैं। वह चाहें तो आरपीआई में आ जाएं। साथ ही बसपा प्रमुख मायावती भी अगर आरपीआई में आ जाएं तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई के सवाल पर रामदास आठवले ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ टैक्स कम करने चाहिए।

किसान बेचेंगे १०० रुपये लीटर दूध, कृषि कानूनों और पेट्रोल-डीजल के दाम के विरोध में खाप पंचायत का फैसला

हिसार (आईएनआईएस) देश का राजधानी नई दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान संगठनों के आंदोलन के बीच हरियाणा की एक खाप पंचायत ने बड़ा फैसला लिया है। हिसार में एक खाप पंचायत ने शनिवार को तय किया कि वो औषि कानूनों और बढ़े हुए पेट्रोल-डीजल और गैस के दाम के विरोध में दूध के दाम में बढ़ोतरी करेंगे। पंचायत के प्रवाक्ता ने कहा कि हमने १००/- लीटर की कीमत पर दूध देने का फैसला किया है। हम डेयरी किसानों से सरकारी सहकारी समितियों को समान मूल्य पर दूध बेचने का आग्रह करते हैं।

उन्होंने कहा, ष्हमने निर्णय लिया है कि जो दूध है ये भी किसान पैदा करता है, मजदूर पैदा करता है। पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव ५० रुपये। आपस में जो दूध लिया-दिया जाएगा, वो उसी रेट में दिया जाएगा परंतु जो निगम हैं, जिस तरह डेरी हैं तो इनको १०० रुपये किलो से कम हम लोग किसान नहद्र देंगे।ष सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान ने कहा कि हमने दूध डेरी में बंद करने का निर्णय लिया है। डेरी में जो दूध देगा वो भाई किसान नही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस व स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रदान ने २१ फरवरी को तेल के बढ़ते दाम को लेकर कहा था।

Ramagya Distributors Pvt. Ltd.
(Deals in Writing and Printing Papers)
Gwynne Road ,Aminabad ,Lucknow
Phone:0522-4001081,9415018235
We Deal In : *All Writing and Printing Paper Solutions
*Call For Printing and Writing Paper Solutions.

KHUSHI FOUNDATION
Smile for Every Face
C-695,Ist Floor,Sector-6,Indira Nagar,Lucknow-226016,
www.khushifoundation.net

जम्मू में कांग्रेस नेताओं की मोर्चाबंदी से टीम राहुल गांधी नाखुश, पूछा- क्या इससे बीजेपी को नहीं होगा फायदा?

नई दिल्ली (आईएनआईएस) जम्मू में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के जमावड़े को लेकर दिल्ली में भी हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक, सीनियर नेताओं की मोर्चाबंदी से टीम राहुल गांधी नाखुश है। राहुल गांधी की टीम को शिकायत है कि विधानसभा चुनावों में प्रचार की बजाय सीनियर नेता अपनी शिकायतों को तरजीह दे रहे हैं जबकि राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन पर मेहनत कर रहे हैं।

सीनियर नेताओं द्वारा उठाए गए इस कदम पर टीम राहुल गांधी का मानना है कि मोर्चाबंदी से कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लग सकता है। राहुल गांधी की टीम ने इससे बीजेपी को फायदा होने की संभावना जताई है। उनकी टीम ने सवाल उठाया है कि क्या इससे बीजेपी को फायदा नही होगा। टीम राहुल गांधी का कहना है कि इस मोर्चाबंदी को कांग्रेस के वफादार सिपाही कभी नहद्र भूलेंगे। कांग्रेस के जी-२३ गुट के नेताओं ने गांधी परिवार के खिलाफ खुली मोर्चाबंदी कर दी है। जम्मू में जी-२३ के नेता एक मंच पर भगवा पगड़ी पहनकर जुटे। इस मंच से कांग्रेस के दिग्गजों ने अपने नेतृत्व पर सवाल उठाया है। इन लोगों ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने को लिए जो भी बलिदान करना होगा हम करेंगे। जम्मू के इस कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, मनीष तिवारी, और आनंद शर्मा भी शामिल हुए हैं।कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई पर भी सवाल उठाया और कहा कि हम आजाद से आजाद नहीं होना चाहते थे पार्टी ने उनके अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहद्र किया? उन्होंने कहा-सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है। अब इकट्ठा होकर हमें इसे मजबूत करना है।

वही, आनंद शर्मा ने कहा कि हमसे कोई भी खिड़की से नहद्र आए। उन्होंने कहा, 'सब दरवाजे से आए हैं। हमारी पहचान कांग्रेस की रही है और कांग्रेस भी हमारी पहचान है। ये अधिकार किसी की नही कि हमें कोई बताए कि कांग्रेस क्या है। यह हक किसी का नहद्र है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है। हम बनाएंगे कांग्रेस को। पिछले १० सालों में कांग्रेस कमजोर हुई है आनंद शर्मा ने कहा कि श्दो भाई अलग-अलग मत रखते हों, तो इसका मतलब यह नहद्र है कि घर टूट जाएगा। या भाई, भाई का दुश्मन हो जाता है, ऐसा तो नही हो जाता है। अगर कोई अपना मत न व्यक्त करे कि उसका कोई क्या मतलब न निकाल ले, फिर वह घर मजबूत नही रहता है श वही, मनीष तिवारी ने कहा कि तमाम राष्ट्रवादी सोच के लोगों को एक मंच पर आना होगा और उसमें आजाद साहब की भूमिका काफी बड़ी होगी।

बैठक की शुरुआत में गुलाम नबी आजाद ने कहा, श्पिछले ५-६ साल से इन सभी दोस्तों ने जम्मू-कश्मीर को लेकर, यहां की बेरोजगारी, राज्य का दर्जा छीनने, इंडस्ट्री को खत्म करने, शिक्षा और जीएसटी लागू करने के मुद्दे लेकर संसद में मुझसे कम नही बोला है। चाहे जम्मू हो या कश्मीर या लद्दाख, हम सभी धर्म, लोगों और जाति का सम्मान करते हैं। हर एक समान रूप से सभी का आदर करते हैं। यह हमारी ताकत है और इसे हम आगे भी जारी रखेंगे।

धर्म और जाति के नाम पर लगातार नफरत फैला रही है भाजपा : अखिलेश यादव

वाराणसी (जिला सवाददाता) समाजवादी पाटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में धर्म और जाति के नाम पर लगातार नफरत फैला रही है। संत रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारे देश में लोग एक-दूसरे के धर्म और संप्रदाय पर भरोसा करते हैं, यह हमारे देश की खूबी रही है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाए कि भारत की संस्कृति और एकता के बीच में कोई सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम कर रहा है तो वे भाजपा के लोग हैं।

उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में आयोजित एक कार्यकर्ता शिविर में हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा संकट का रूप लेने वाला है और यदि हमने देश को इस संकट से नहद्र उबारा तो हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा का सामना करना पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा रास्ता धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का है। भाजपा सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों से हमारी अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों का नुकसान हुआ है।उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकारें नए एसेट्स बनाने की बजाय पुराने एसेट्स बेचने में लगी हुई हैं। कांग्रेस से दोबारा गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पाटी किसी भी बड़ी पाटी से गठबंधन नहद्र करेगी।

गौरतलब है कि अखिलाश यादव ने वाराणसी में सीरगोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर पहुंच कर श्रद्धासुमन अर्पित किया और कहा कि संत रविदास की समता, बंधुत्व, सौहार्द और भेदभाव के विरोध की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पाटी औतसंकल्प है।

समाजवादी पाटी के प्रदेश मुख्यालय से शनिवार को जारी बयान के अनुसार, वाराणसी में मंदिर के मुख्य द्वार पर रैदासियों ने अखिलेश यादव का स्वागत किया और मंदिर के मुख्य रैदासी स्वामी निरंजन दास ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया। यादव ने लंगर में प्रसाद भी ग्रहण किया। यादव ने कहा, ''संत रविदास जी समाज सुधारक, महान क्रांतिकारी और स्वतंत्र चिंतक थे और उन्होंने पाखंड और कुरीतियों का डटकर विरोध किया। समाज में एकता, भाईचारा और समानता के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा, उनके अनुसार मानव सेवा ही वास्तविक धर्म है।''

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''संत रविदास के अनुयायी देश के सभी हिस्सों में मौजूद हैं। संत रविदास श्रम की प्रतिष्ठा को सवोपरि मानते थे और उन्होंने भाईचारा, सद्भावना, समानता और करूणा का संदेश दिया। 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' का सूत्र देने वाले संत रविदास का जीवन दर्शन पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है।''

उत्तराखंड में अब बेटियों के नाम से जाने जाएंगे घर, नैनीताल से हुई शुरुआत

नई दिल्ली (आईएनआईएस) बालिकाओं को अपेक्षाकृत अधिक सम्मान देते हुए उत्तराखंड सरकार ने 'घरैकि पहचाण चेलिक नाम' कार्यक्रम की शुरूआत की है। इस परंपरा के तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की पट्टिका लगाई जाएगी। राज्य में यह शुरूआत नैनीताल जिले की नैनीताल नगरपालिका से की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को उत्तराखंड में एक कदम और आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परंपरा के तहत परिवार की सबसे छोटी बेटी के नाम पर उस घर की पट्टिका लगाई जाएगी, ताकि घर की पहचान बिटिया के नाम पर हो सके। प्रथम चरण में इस नई परंपरा की शुरूआत नैनीताल जिले की नैनीताल नगरपालिका से की गई।

नैनीताल जिले के सभी विकासखंडों का एक-एक ग्राम चयनित किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि पट्टिका में बेटी के नाम की पट्टिका बनाए जाने में ऐपण कला का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे स्थानीय कला को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह छोटी सी कोशिश एक दिन अभियान बनेगी और हर घर का नाम बेटी के नाम पर होगा। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए औत संकल्प है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार ने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सहखातेदार का अधिकार दिया है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक से लोन मिल सकेगा और वे स्वावलंबी बन सकेंगी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमें महिलाओं को समान अधिकार और समान अवसर देने होंगे। हमारी सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक, मानसिक के साथ ही शारीरिक दृष्टि से भी सशक्त बनाया जा रहा है। उनके सम्मान में कोई कसर बाकी नहद्र रखी जाएगी। समारोह में कई महिलाओं को उनके बेटी के नाम की पट्टिका घर पर लगाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदान की।

गौकशी का झूठा आरोप लगाकर घूस लेने वाले दारोगा पर योगी सरकार ने लिया एक्शन, किया सस्पेंड

बुलन्दशहर (आईएनआईएस) उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस तरह से यूपी पुलिस धर्म, जाति-पात को दरकिनार करके लोगों को इंसाफ दिला रही है और रिश्वत खोर पुलिस कर्मियों पर एक्शन ले रही है, उसका ताजा मामला यूपी के बुलन्दशहर जिले से सामने आया है। बुलन्दशहर जिले के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एक मुस्लिम शख्स से रिश्वत लेने के आरोप में एसएचओ रमाकांत को सस्पेंड कर दिया है। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह को पिछले कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी कि थाना जहांगीराबाद के एसएचओ रमाकांत पैसे लेकर मामलों को रफा-दफा कर रहे हैं तो कभी बेकसूर लोगों को भी फंसाने की धमकी के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं।

इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने भुल्लन नाम के शख्स पर गोकशी का सामान ले जाने का आरोप मढ़कर उससे १५ हजार की रिश्वत वसूली। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह को पता लगा कि भुल्लन नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति जिसके गांव जहांगीराबाद में कुछ समय पहले गौकशी के आरोप में दो लोग पकड़े गए थे और २ फरार थे। उस मामले में शक के आधार पर थाना इंचार्ज ने भुल्लन को बुलाया और थाने में बैठाकर रखा, हालांकि इंस्पेक्शन में उसका गौकशी से कोई लेना देना सामने नहद्र आया, लिहाज उसे छोड़ दिया जाना चाहिए था लेकिन उससे १५००० रुपए रिश्वत के तौर पर पेट्रोल भरवाने के नाम पर ले लिए गए, इसकी जानकारी एसएसपी को लगी उन्होंने खुद अपनी टीम के साथ थाने और थाने के बगल में एसएचओ के आवास पर दरवाजे बाहर से बंद करके रेड की। रेड के दौरान पता लगा कि कचरा फेंकने के बहाने पीछे जंगल मे पैसे छिपा दिए।

हालांकि जंगल से पैसे बरामद अब तक नहद्र हुए है, लेकिन पुलिस का कहना है रिश्वत लेने के पुख्ता सबूत हैं, लिहाजा एसएचओ रमाकांत यादव को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की तफ्तीश जारी है। उम्मीद है कई और रिश्वत के मामले सामने आ सकते हैं। बुलन्दशहर के जहांगीराबाद थाने के एसएचओ रमाकांत यादव ने जिस मुस्लिम शख्स भुल्लन को गौकशी का सामान गाड़ी में इधर से उधर ले जाने के शक में हिरासत में लिया और थाने में जबरदस्ती बैठाकर रखा और केस में शामिल न होने के बावजूद १५००० रुपए लेकर छोड़ा। जिसके बाद एसएसपी ने कारवाही करते हुए रेड की और फिर एसएचओ को सस्पेंड किया।

भुल्लन से इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव बात की। भुल्लन का कहना है वो गाड़ी चलाता है, गाड़ी मैकेनिक के यहां थी, वहां एसएचओ आए और थाने ले गए, वहां पैसों की बात करने लगे कि जेल भेज देंगे। मैंने कहा पैसे नहद्र हैं, मैंने कुछ गलत नहद्र किया, चाहो तो जेल भेज दो। फिर अगले दिन गांव वाले आए और मुझे छुड़ाकर ले गए, मुझे नहद्र पता कितने पैसे दिए। योगी राज में पुलिस बिना जात-पात, धर्म के आधार पर नहद्र बल्कि कानून के हिसाब से काम कर रही है, जैसे एसएचओ को सस्पेंड किया और रेड की। इस पर कहना है कोई हिन्दू मुस्लिम नही बल्कि प्रदेश में कानून के हिसाब से काम हो रहा है। अगर पक्षपात होता तो मैं जेल में होता। सन्तुष्ट है सीनियर अफसर की कार्यवाही से जो एसएचओ को सस्पेंड किया और रेड की, जो गलत करेगा उसपर एक्शन होना चाहिए, चाहे मैं हूं या पुलिस वाले।

सरकार को अपना 'अहंकार' छोड़कर ईंधन करों को कम करना चाहिएः कांग्रेस

नयी दिल्ली। (आईएनआईएस) कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आम आदमी की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि उसे अपना ष्अहंकारष छोड़कर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एलपीजी) पर लगाए गए करों को कम करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार को पेट्रोल और डीजल पर क्रमशरू २३.७८ रुपये और २८.३७ रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त करों को तुरंत हटाना चाहिए। इससे ईंधन की कीमतों को नीचे

लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर करों को कम करने के लिए सरकार से अपील करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में आयी गिरावट के बीच आम आदमी पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से परेशाना है।

सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस की मांग को दरकिनार कर सकते हैं लेकिन उन्हें कम से कम अपने उन बयानों को याद करना चाहिए जो उन्होंने केंद्र में संप्रग शासन के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दिया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की सलाह पर भी गौर करना चाहिए कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का व्यापक प्रभाव होगा। संप्रग शासन के दौरान मोदी के बयानों का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा, ''कांग्रेस और देश का आपसे आग्रह है कि संप्रग कार्यकाल के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए आप अपनी खुद की आवाज सुनें।'' उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर से कर हटाने को लेकर दुविधा में होने संबंधी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान को लेकर उन पर भी निशाना साधा।

सिंघवी ने सवाल किया, ''कौन सा धर्म संकट और बाधा है कि वित्त मंत्री भी कर में कमी नहद्र कर पा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं? '' सिंघवी ने कहा कि यह शर्मनाक है कि मई २०१४ से कच्चा तेल ३६.२ प्रतिशत सस्ता है, जबकि मोदी सरकार में पेट्रोल और डीजल क्रमशरू २७.५ और ४२.२ प्रतिशत महंगा है। उन्होंने कहा कि यह ष्उलटा चलन' है जहां वैश्विक दरें घट रही हैं, लेकिन घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं। सिंघवी ने दावा किया कि इस सरकार ने पिछले २० दिनों में १४ बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की। उन्होंने आरोप लगाया, श्मोदी सरकार लोगों के लिए सबसे महंगी सरकार रही है, जिसने लोगों पर भारी कर लगाया है। यह अभिमानी सरकार लोगों की समस्याओं को स्वीकार करने या उन्हें कोई राहत देने को तैयार नहद्र है। उसने सिर्फ श्फूट डालो, धोखा दो, ध यान भटकाओ और भूल जाओ' की कोशिश की है और ये श्हम दो, हमारे दो सरकारश के पसंदीदा शब्द हैं।''

कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सरकार ने पिछले छह वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाकर २१.५ लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। उन्होंने कहा कि मई २०१४ में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत १०८ डॉलर प्रति बैरल थी और दिल्ली में पेट्रोल ७१.५१ रुपये प्रति लीटर तथा डीजल ५७.२८ रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा था। कांग्रेस नेता ने कहा कि २५ फरवरी, २०२१ को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ६५.७० डॉलर प्रति बैरल है, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर ९१.१७ रुपये और डीजल की कीमत ८१.४७ रुपये प्रति लीटर है।

उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासन में पेट्रोल की दरों में ८२० प्रतिशत और डीजल में २५८ प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले तीन महीनों में रसोई गैस की कीमत में २०० रुपये की वृद्धि हुई है। सिंघवी ने कहा, श्हम पेट्रोल और डीजल पर क्रमशरू २३.८७ रुपये और २८.३७ रुपये प्रति लीटर की तत्काल कटौती की मांग करते हैं, यह कोई एहसान नहद्र है बल्कि महामारी के समय लोग राहत के हकदार हैं।'

राकेश टिकैत सहारनपुर में करेंगे महापंचायत, जानिए मार्च में कहां-कहां होगी रैलियां, ये रही लिस्ट

गाजीपुर बॉर्डर (आईएनआईएस) कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को तीन महीने हो चुके हैं। ऐसे में मार्च महीने में दर्जन भर महापंचायत आयोजित की जा रही है, ताकि इस आंदोलन को और धार दी जा सके और लोगों को इन कानूनों के बारे में जागरूक किया जा सके। लेकिन बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार और किसान फिर से बातचीत की टेबल पर क्यों नहद्र बैठ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से २८ फरवरी से लेकर २२ मार्च तक का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसमें देश के विभिन्न जगहों पर महापंचायतें अयोजित की जाएंगी।

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इन सभी महापंचायतों में शामिल होंगे। आज रविवार २८ फरवरी को यूपी के सहारनपुर में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे, वहद्र १ मार्च को उधमसिंह नगर के रुद्रपुर की महापंचायत में शिरकत करेंगे। २ मार्च को राजस्थान के झुंझनू में, ३ मार्च को राजस्थान के ही नागौर में महापंचायत होगी। इसके बाद ५ मार्च को यूपी के इटावा स्थित सैफई तो ६ मार्च को तेलंगाना में आयोजित कार्यक्रम में राकेश टिकैत शामिल होंगे।

७ मार्च को वह फिर से गाजीपुर बॉर्डर के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, इसके बाद ८ मार्च को एमपी के श्योपुर में शिरकत करेंगे, १० मार्च को यूपी के बलिया में किसान आयोजित महापंचायत में शामिल होंगे। १२ मार्च को राजस्थान के जोधपुर तो १४ मार्च को मध्यप्रदेश के रीवा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे आखिर में २०, २१ और २२ मार्च को कर्नाटक में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

किसानों की तरफ से यह साफ कर दिया है कि जब तक सरकार बात नहद्र करती है तब तक इसी तरह से औषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। सरकार और किसानों की ११ दौर की बातचीत के बाद अभी तक फिर से बातचीत के कोई संकेत नजर नहीं आ रहें है, ऐसे में किसान बॉर्डर पर ही बैठे हुए है, इसपर जब राकेश टिकैत से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, आम जनता को साथ में आना चाहिए, आम जनता को ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए ज़ब राकेश टिकैत से फिर पूछा गया कि आप ही सरकार से बात नहद्र करेंगे तो हल कैसे निकलेगा? राकेश टिकैत ने कहा कि, हम तो बात कर रहे हैं, हमने संदेश भी भेजा है कि ये हमारे मुद्दे हैं, बात करें, लेकिन अभी तक कोई जवाब नही आया है। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता के साथ-साथ तमाम राजनीतिक दल भी किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी-अपनी किसान महापंचायत कर रहे हैं।

भारतीय रेलवे ने दी गुड न्यूज़, किया कई ट्रेनों का ऐलान, ये रही पूरी डिटेल

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए कई और नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे द्वारा इन ट्रेनों का ऐलान

वडोदरा-जामनगर, नांदेड-श्रीगंगानगर, मुंबई सेंट्रल- वलसाड रूट पर किया गया है। इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को कोविड-१९ को रोकने के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली इन विशेष ट्रेनों की अधिक जानकारी के लिए आप **www-enquiry-indianrail-gov-**पद पर विजिट कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं भारतीय रेलवे द्वारा किन ट्रेनों का ऐलान किया गया है।

०२९५६ वडोदरा से जामनगर सुपरफास्ट स्पेशल (हफ्ते में ५ दिन- रविवार और बुधवार को नही चलेगी)- ये स्पेशल ट्रेन १ मार्च से हर दिन दोपहर में १५.५० बजे वडोदरा रेलवे स्टेशन से चलेगी और उसी दिन रात में २३.३५ बजे जामनगर पहुंचेगी। अपने रूट पर ये ट्रेन आणंद, नडियाड, अहमदाबाद, साबरमती, चांदलोडिया, विरमगाम, सुरेंद्रनगर, थान, वांकानेर, राजकोट और हापा रेलवे स्टेशन पर रुकेगी।

०२९६० जामनगर से वडोदरा सुपरफास्ट स्पेशल (हफ्ते में ५ दिन- रविवार और बुधवार को नही चलेगी)- ये स्पेशल ट्रेन १ मार्च २०२१ हर दिन सुबह के ४.४५ बजे जामनगर रेलवे स्टेशन से चलेगी और उसी दिन दोपहर में १२.३० बजे वडोदरा पहुंचेगी। अपने रूट पर ये ट्रेन हापा, राजकोट, वांकानेर, सुरेंद्रनगर, विरमगाम, चांदोलोडिया, साबरमती, अहमदाबाद, नडियाड और आणंद रेलवे स्टेशन पर रुकेगी।

०७६२३ नदिड से श्रीगंगानगर स्पेशल (हफ्ते में एक दिन)- विशेष किराए के साथ- ये स्पेशल ट्रेन १ अप्रैल से नांदेड़ रेलवे स्टेशन से हर गुरुवार को सुबह ६.५० बजे चलेगी और अगले दिन १९.२० बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। नांदेड से चलने के बा दये ट्रेन अमलनेर, नंदुरबार, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, नडियाड, अहमदाबाद, महेसाणा और पालनपुर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी।

०७६२४ श्रीगंगानगर से नादेड़ स्पेशल (हफ्ते में एक दिन)- विशेष किराए के साथ- ये स्पेशल ट्रेन ३ अप्रैल २०२१ से हर शनिवार को श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से दोपहर में १२.३० बजे चलेगी और सोमवार को २.३० बजे नांदेड़ पहुंचेगी। श्रीगंगानगर से चलने के बाद ये ट्रेन पालनपुर, महेसाणा, अहमदाबाद, नडियाड, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नंदुरबार और अमलनेर पर रुकेगी।

०६०२३ मुंबई सेंट्रेल से वलसाड स्पेशल (प्रतिदिन)- ये स्पेशल ट्रेन १ मार्च से मुंबई सेंट्रेल रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन शाम के १८.१० बजे चलेगी और २३.०५ बजे वलसाड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। अपने रूट पर ये ट्रेन दादर, बोरिविली, विरार, वैतरना, सफाले, केलवे रोड, पालघर, बोईसर, वनगांव, दहानु रोड, घोलवड, उमरगांव रोड, संजान, भीलड़, करंबेले, वापी, उदवाड़ा, पारडी और अतुल रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। ०६०२४ वलसाड से मुंबई सेंट्रल स्पेशल (प्रतिदिन)- ये स्पेशल ट्रेन १ मार्च से हर दिन सुबह के ०४.४० बजे वलसाड रेलवे स्टेशन से चलेगी और ६.१५ बजे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। अपने रूट पर ये ट्रेन अतुल, पारडी, उदवाड़ा, वापी, करंबेले, भीलड़, संजान, उमरगांव रोड, घोलवड, दहानु रोड, वनगांव, बोईसर, पालघर, केलवे रोड, सफाले, वैतरना, विरार, बोरिविली और बांदर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी।

सम्पादकीय

असहमति का अधिकार

हाल ही में देश में किसानों द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में सवोच्च न्यायालय में पिछले वर्ष दिल्ली के शाहीन बाग क्षेत्र में हुए विरोध प्रदर्शनों पर एक समीक्षा याचिका दायर की गई है। न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति को विरोध ा करने का पूर्णध्अनिवार्य अधिकार नहद्ध है और यह स्थान तथा समय के संदर्भ में प्राधिकारी के आदेशों के अधीन हो सकता है।

यह राज्य की सुरक्षा, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्त्व तथा नैतिकता के बीच की रस्साकशी पर एक बार पुनः हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जहाँ एक तरफ यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे की कोई भी विरोध प्रदर्शन हिंसक अराजकता में न बदलने पाए। वहद्ध दूसरी तरफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज की पहचान हैं, जो यह मांग करता है कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा आम जनता की आवाज सुनी जानी चाहिये तथा उचित चर्चा और परामर्श के बाद निर्णय लिये जाने चाहिये। इस दुविधा के बावजूद भारतीय समाज के लोकतांत्रिक ताने-बाने को संरक्षित करने के लिये देश के लोकतांत्रिक प्रणाली से जुड़े हितधारकों का यह उत्तरदायित्त्व है कि संविधान के अनुच्छेद १९ के तहत प्रदान किये गए स्वतंत्रता के किसी भी अधिकार को गंभीर रूप से क्षति नहद्ध पहुँचनी चाहिये।

मौलिक अधिकाररू भारतीय संविधान में नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध ा प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद १९(१)() वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा अनुच्छेद १९(१)(इ) नागरिकों को बगैर हथियार के एवं शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होने का अधि ाकार देता है। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि उसके (भारत के) उपनिवेशवाद-विरोध ाी संघर्ष से बनी है, जिसके भीतर एक राजनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र और लोकतांत्रिक संविधान के बीज बोए गए थे। भारतीयों ने औपनिवेशिक नीतियों और कानूनों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने तथा उनके खिलाफ एक सार्वजनिक राय बनाने के लिये बहुत ही कठोर एवं लंबा संघर्ष किया है। शक्ति के दुरुपयोग की जाँचरू संघ या समूह बनाने का अधिकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिये समूह बनाने हेतु आवश्यक है- उदाहरण के लिये सामूहिक रूप से सरकार के फैसलों को चुनौती देना और यहाँ तक कि शांतिपूर्वक तथा कानूनी तौर पर सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास, न केवल शक्ति के दुरुपयोग की जाँच करने बल्कि इस पर प्रश्न उठाने आदि मामलों में। शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार राजनीतिक दलों और नागरिक निकायों जैसे- विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र समूहों को प्रदर्शनों, आंदोलन तथा सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से सरकार के निर्णयों पर प्रश्न उठाने, आपत्ति जताने व निरंतर विरोध आंदोलनों को शुरू करने में सक्षम बनाता है। लोग लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं और सरकारों के निर्णयों की लगातार निगरानी करते हैं, जो सरकारों को उनकी नीतियों और कार्यप्रणाली के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जिसके बाद संबंधित सरकार परामर्श, बैठकों और चर्चा के माध्यम से अपनी गलतियों को चिह्नित करते हुए उन्हें सुधारती है। सुप्रीम कोर्ट का पर्यवेक्षणरू रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारतीय संघ और अन्य मामले (वर्ष २०१२) में सवोच्च न्यायालय ने कहा था, नागरिकों का इकठ्ठा होकर शांतिपूर्ण विरोध करना एक मौलिक अधिकार है जिसे एक मनमानी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई द्वारा छीना नहीं जा सकता है। सरकार के प्रस्तावों या निर्णयों को चुनौती देने के लिये की गई कोई भी सार्वजनिक कार्रवाई तब तक ही संवैधानिक रूप से वैध है, जब तक कि यह शांतिपूर्वक ढंग से की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद १९(२) लोगों के बगैर हथियार के और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाता है। ये प्रतिबंध भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, या उकसावे आदि मामलों में लगाए जा सकते हैं। हालाँकि हालिया समीक्षा याचिका में याचिकाकर्त्ताओं ने कहा कि शाहीन बाग मामले में सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चितकालीन कब्जे के खिलाफ दिया गया फैसला पुलिस के लिये वास्तविक कारणों से प्रेरितध संबंधित विरोध प्रदर्शनों के मामले में अत्याचार करने का एक लाइसेंस साबित हो सकता है।

गौरतलब है कि हाल ही में न केवल प्रदर्शनकारी किसानों बल्कि उनके समर्थक जिनमें हास्य कलाकार और पत्रकार भी शामिल थे, पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकारों के प्रयोग पर कोई भी मनमाना अवरोध - उदाहरण के लिये धारा १४४ लागू करना आदि असंतोषध्असहमति को सहन करने में सरकार की अक्षमता को दर्शाता है। सक्रिय न्यायपालिकारू संवैधानिक मामलों में एक निष्पक्ष और प्रभावी न्यायिक तंत्र सड़कों पर होने वाले आंदोलनों को प्रभावी रूप से रोक सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जब निष्पक्ष मुकदमों के माध्यम से मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है, तो उस स्थिति में सामाजिक आंदोलन कम आक्रामक और कम विरोधी हो सकते हैं। इसके अलावा न्यायालयों को समय पर अधि ानिर्णयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि समय पर कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत विवादित कानूनों की वैधता पर विचार या अधिनिर्णयन किया गया होता, तो सड़कों पर आंदोलनों की तीव्रता को संभवतः कम किया जा सकता था। सार्वजनिक जाँच प्रणाली की स्थापनारू यूनाइटेड किंगडम में एक मजबूत सार्वजनिक जाँच प्रणाली मौजूद है जो पारिस्थितिक मांगों को संसाधित करने और उन्हें राजनीतिक प्रणाली में एकीकृत करने का कार्य करती है।

राम मंदिर के लिए २,१०० करोड़ रुपये से अधिक जमा हुए : ट्रस्ट

अयोध्या (जिला सवाददाता) अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए ४४-दिवसीय धन जुटाने का अभियान

शनिवार को समाप्त हो गया। इस पहल से जुड़े ट्रस्ट ने कहा कि उन्होंने २,१०० करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह कर लिया है। १५ जनवरी को क्राउडफंडिंग अभियान की शुरुआत से पहले, ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर के निर्माण के लिए १,१०० करोड़ रुपये एकत्रित करने का अनुमान लगाया था, लेकिन ट्रस्ट को अनुमान से १,००० करोड़ रुपये से अधि ाक की राशि मिली।

श्री रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, गोविंद देव गिरि ने संवाददाताओं से कहा, ष्धन जुटाने का अभियान भारत के दूर-दराज के गांवों क ` निवासियों स हि त सभी ध ार्मिक वगी के उदार योदानकर्तओ के उदार योगदान के सा थ ा समाप्त हो गया है। शनिवार शाम तक दान में मिली राशि २,१०० करोड़ रुपये को पार कर गई।ष

गिरि ने पिछले साल दिसंबर में राम जन्मभूमि पर पूरे परिसर के निर्माण के लिए १,१०० करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था, जबकि मंदिर के निर्माण की लागत ३००-४०० करोड़ रुपये आंकी थी। अयोध्या के साधुओं ने अब मंदिर ट्रस्ट को अयोध्या के विकास के लिए अधि ाशेष धन का उपयोग करने की सलाह दी है और करोड़ों राम भक्तों द्वारा दान किए गए धन के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है।

हालांकि, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा, ष्मंदिर परिसर के निर्माण का बजट अंतिम नहद्ध है और यह निर्माण पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। तपस्वी छावनी के स्वामी परमहंस आचार्य ने कहा, ष्ट्रस्ट को माता सीता के नाम पर अयोध्या में संस्औत विश्वविद्यालय स्थापित करने और मंदिर शहर में दूध ा की मुफ्त आपूर्ति के लिए एक गौशाला स्थापित करने के लिए अतिरिक्त धन का उपयोग करना चाहिए।ष

निमोही अखाड़े के महंत धनेन्द्र दास ने कहा, ष्भगवान राम के नाम पर करोड़ों भारतीयों ने धन का दान किया है और अतिरिक्त धन का उपयोग अयोध्या और उसके मंदिरों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।ष हनुमान गढ़ी मंदिर के पुजारी, महंत राजू दास ने कहा कि धन का इस्तेमाल अयोध्या में पुराने मंदिरों को पुनजीवित करने के लिए किया जा सकता है।

बीजेपी विधायक की आत्महत्या की धमकी के बाद ओडिशा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित

भुवनेश्वर (आईएनआईएस) ओडिशा विधानसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पाटी के एक विधायक द्वारा आत्महत्या

की धमकी दी। वहद्ध, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी अध्यक्ष के आसन के पास जाकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। रिपोर्ट्र्स के मुताबिक, बीजेपी विधायक के खुदकुशी कर लेने की ध ामकी और कांग्रेस विधायक दल के नेता के अध्यक्ष के आसन के समीप धरना पर बैठ जाने के बाद सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद के सत्र तक के लिए स्थगित कर दी गई।

रिपोर्ट्र्स के मुताबिक, ये दोनों विध ाायक राज्य की विभिन्न मंडियों में किसानों से धान की तत्काल खरीद की मांग कर रहे थे। यह मुद्दा प्रश्नकाल में तब उठा जब देवगढ़ से भारतीय जनता पाटी के विधायक सुभाषचंद्र पाणिग्रही ने घोषणा की कि केंद्रीऔत टोकन प्रणाली के लागू होने के बाद मंडियों में अपना धान नहद्ध बेच पाए किसानों की परेशानियों को लेकर वे आत्मदाह से भी नहद्ध हिचकेंगे। पाणिग्रही ने कहा, 'जब तक धान की फसल बिक्री के लिए तैयार होती है, तब तक टोकन की अवधि खत्म हो चुकी होती है, इससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके चलते किसान आंदोलनरत हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।'

पाणिग्रही ने कहा, 'मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसान खुदकुशी की धमकी दे रहे हैं क्योंकि वे अपना धान नहद्ध बेच पा रहे हैं। इसलिए, जब किसान आत्मदाह के लिए तैयार हैं, तो उनके प्रतिनिधि के पास धान की खरीद में असमर्थता के खिलाफ सरकार के विरोध के लिए वही प्रक्रिया अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहद्ध है।' वहद्ध, प्रश्नकाल शुरू होने पर कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा धरने पर बैठ गए। मिश्रा ने कहा, 'हम सरकार से साफ जवाब चाहते हैं। अध्यक्ष को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने और मुद्दे को तुरंत हल करने दें।' व्यवध ाान के बीच सदन नहद्ध चला पाने पर विधानसभा अध्यक्ष एस. एन. पात्रो ने ४ बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।

पीएम मोदी की तस्वीर और १९ सैटेलाइट्र्स को पी.एस.एल.वी. -सी ५१ लेकर भरी उड़ान, अंतरिक्ष में गूंजेगा गीता का संदेश

श्रीहरिकोटा से पी.एस.एल.वी.-सी ५१ के जरिये एमेजोनिया-वन और १८ अन्य्य उपग्रहों को लॉन्च किया। बता दें कि इसके लॉन्च होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। भारतीय रॉकेट पीएसएलवी-सी५१ को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर (एसडीएससी) से एक लॉन्च पैड के सहारे रवाना किया गया। इस रॉकेट में ६३७ किलो के ब्राजीलियाई उपग्रह अमेजोनिया-१ सहित १८ अन्य सैटेलाइट्र्स भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें से १३ अमेरिका से हैं। इस लॉन्च की खास बात यह है कि इसके साथ भगवदगीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आसमान की ऊंचाइयों में पृथ्वी का चक्कर काटेगी। स्पेस किड्ज इंडिया ने अपने सतीश धवन सैटेलाइट के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी है। स्पेस किड्ज इंडिय की वेबसाइट के मुताबिक, यह कदम पीएम की आत्मनिर्भर पहल और निजी कंपनियों के अंतरिक्ष की राह खोलने वाले निर्णय से एकजुटता दिखाने के लिए उठाया जा रहा है। इस सैटेलाइट के जरिए स्पेस किड्ज इंडिया अंतरिक्ष में रेडिएशन पर रिसर्च करेगा। साल २०२१ में भारत का यह पहला अंतरिक्ष अभियान पीएसएलवी रॉकेट के लिए काफी लंबा होगा क्योंकि इसके उड़ान की समय सीमा १ घंटा, ५५ मिनट और ७ सेकेंड की होगी।

योजनाओं का लाभ उठाएं–जच्चा–बच्चा को स्वस्थ बनाएं

• गर्भावस्था की समुचित देखभाल से लेकर सुरक्षित प्रसवतक का है पूरा इंतेजाम • हर कदम पर जागरूक रहकर घर में खुशियाँ लायें

हरदोई, (ऋचा द्विवेदी)–सुरक्षित प्रसव और जच्चा–बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग हरसंभव कोशिश में जुटा है । सरकार भी ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटी है ताकि गर्भवती को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करने पड़े, क्योंकि हरगर्भवती का एक ही सपना होता है कि एक स्वस्थ औरत दुरुस्त बच्चा उसकी बांहों में हो।गर्भवती का यह सपना तभी साकार हो सकता है जब वह स्वास्थ्य विभाग की इन योजनाओं का लाभ उठाने को आगे आये और क्षेत्रीय आशा, एएनएम और चिकित्सक की सलाह को पूरी तरह से गाँठ बाँधले।

प्रजनन एवं बालस्वास्थ्य (आरसीएच) के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. स्वामी दयाल का कहना है–गर्भवती को सबसे पहले अपना पंजीकरण स्वास्थ्य केंद्र पर कराना चाहिए । चार प्रसव पूर्वजांचें करानी चाहिए ताकि यदि कोई जटिलता है तो समय से उसका प्रबंधन हो सके। उच्च खतरे वाली गर्भावस्था का पता लगते ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता मात शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी) पर लाल बिंदी लगा देते हैं जिसे देखकर चिकित्सालय में प्राथमिकता के आधार पर इलाज मुहैया कराया जाता है।

प्रसव, जहाँ तक संभव हो अपने सबसे पास के स्वास्थ्य केंद्र पर ही कराना चाहिए जिसका निर्णय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ मिलकर पहले से ही करले ना चाहिए । प्रसव से पहले कुछ आवश्यक तैयारियां जैसे पैसे का प्रबंधन, एम्बुलेंस का नम्बर तथा व्यक्ति की पहचान जिसके साथ आप अस्पताल जायेंगे और स्वास्थ्य सुविधा की पहचान आदि। प्रसव होने के बाद तबतक महिला को अस्पताल से वापस घर नहीं जाना चाहिए जब तक चिकित्सक उन्हें घर वापस जाने को न कहें।

डा. दयाल के अनुसार–ग्रामीण इलाकों में पीएचसी व ब्लाक पर सीएचसीहैं। सामान्य प्रसव तो इन केन्द्रों पर हो जाते हैं लेकिन यदि प्रसव में कोई जटिलता है तो यहाँ से महिला को जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता है। इसके लिए एम्बुलेंस 102 की सुविधा उपलब्ध है। गर्भवती को एम्बुलेंस 102 के द्वारा ही उच्चस्वास्थ्य केंद्र जैसे मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए क्योंकि समय व्यर्थ नहीं होता है और चिकित्सक प्राथमिकता के आधार परमरीज का इलाज करते हैं। ऐसे में गर्भवती महिला/परिवार के सदस्यों को चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह को मानते हुए जिला अस्पताल/उच्च स्तरीय स्वस्थ्य केंद्र पर ले जाना चाहिए ।नोडल अधिकारी बताते हैं–इन सभी सुविधाओं को आम आदमी तक निःशुल्क पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, सुरक्षित मातृ त्वअभियान, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और एम्बुलेंस 102 योजनायें चलायी जा रही हैं। जिसके तहत गर्भधारण करते ही शीघ्र पंजीकरण, चार प्रसवपूर्व जांचें, उच्च खतरे वाली गर्भावस्था की पहचान और प्रबंधन तथा अस्पताल ले जाने सहित यह सभी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध हैं। साथ ही दवाईयाँ, बाकी आवश्यक सामग्री और आवश्यकता पड़ने पर रक्त भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को अस्पताल में प्रसव कराने के लिए 1400 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। डा. स्वामीदयाल के अनुसार–यह सभी योजनायें आमजनता की भलाई के लिए ही हैं। यदि इन योजनाओं का फायदा लेंगे और इनके महत्व को समझते हुए चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सलाह को मानें तो किसी भी अनहोनी से बच सकते हैं क्योंकि "गर्भावस्था जोखिम भरी होती है।

समाज में बदलाव लाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने की खास योजना मिशन शक्ति अभियान

–महिला कल्याण विभाग ने सात करोड़ लोगों को किया जागरूक
–अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 'अनंता' मेगाइवेंट का होगा आयोजन
–महिलाओं की सफलता की कहानी देगी प्रेरणा
–सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार से आएगा समाज में बदलाव
–मिशन शक्ति को नए रूप में जारी रखने के लिए बनेगा रोडमैप

लखनऊ, (आईएनआईएस) सूबे की महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे विशेष मिशन शक्ति अभियान के तहत माच 'माह की थीम" महिलाओं तथा बच्चों में सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार" तय की गयी है । इसके तहत महिलाओं और बच्चों को अपने हक् की लड़ाई में प्रभावी संचार की भूमिका के बारे में जागरूक किया जाएगा । इसके साथ ही समाज में सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से रुढ़िवादी मान्यताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक माहौल बनाया जाएगा । इसके अलावा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महिलाओं की पहचान कर उनकी सफलता की कहानियों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि अन्य महिलाओं के लिए वह प्रेरक की भूमिका अदा करसकें ।

महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति के तहत अब तक करीब 7.06 करोड़ लोगों को जागरूक किया गया है, जिसमें 4,27,45,135 महिलाएं और 2,78,68,302 पुरुष शामिलहैं । महिला कल्याण विभाग के निदेशक और मिशन शक्ति के नोडल अधिकारी मनोजकुमार राय का कहना है कि बहुत से क्षेत्रों में आज भी महिलाओं और बच्चों को भेदभाव व लैंगिक असमानता का शिकार होना पड़ता है, ऐसे में उनको उन स्थितियों से उबारने में प्रभावी संचार की बड़ी भूमिका है । इसी को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ के सहयोग से विषेश सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार माड्यूल तैयार किया गया है और मार्च माह में इसी माड्यूल के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कियाजाएगा । इन कार्यक्रमों में हम बालविकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के साथ सम्मिलित रूप से कार्यकर रहेहैं ।

मनोज कुमार राय- निदेशक , महिला कल्याण

कार्ययोजना के मुताबिक एक से सात मार्च तक प्रत्येक जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की ऐसी महिलाओं की पहचान की जाएगी जिनके प्रयासों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाये हों । इसके साथ ही उनकी कहानी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का काम कर सके । इनमें वह महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं जिन्होंने महिलाओं और बच्चों के विकास, सुरक्षा व संरक्षण के लिए असाधारण कार्यकिये हों । इनमें महिला कल्याण या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की प्रतिभावान, सरवाइवर या प्रेरक महिलाओं को भी शामिल किया जा सकताहै । अनंता : महिला कल्याण विभाग ने इस तरह का सामाजिक बदलाव लाने वाली महिलाओं की कहानियों को आमंत्रित किया है ताकि इनकी कहानियों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आठ माच) पर मेगाइवेंट "अनंता" के माध्यम से टीवी, रेडियो, एफ़एम, कम्युनिटीरेडियो, टाक शो, गोष्ठियों, समाचारपत्रों के माध्यम से जन–जन तक पहुंचाया जासके। सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचार माड्यूल पर प्रशिक्षण : विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मास्टर ट्रेनिंग इसी माड्यूल के आधार पर एक से 10 मार्च के मध्य की जाएगी । इसमें हर जिले के बाल संरक्षण इकाई के एक–एक सदस्य, महिला शक्तिकेंद्र से एक–एक सदस्य, हर जिले से चार–चार मुख्य सेविका को बैचवार प्रषिक्षण दिया जाएगा । यह प्रषिक्षण राज्य स्तर पर ऑनलाइन दिया जाएगा । यही मास्टर ट्रेनर अन्य विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को 10 से 31 मार्च के मध्य प्रषिक्षण प्रदान करेंगे । इसमे जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला शक्तिकेंद्र, वनस्टॉप सेंटर, मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को शामिल किया जाएगा ।

मिषन को सतत रूप से आगे बढ़ाने का रोडमैपहोगातैयार : महिला कल्याण विभाग के आह्वान पर समस्त जिलाधिकारी 'मिशन' को अप्रैल 2021 के बाद भी सतत रूप से जारी रखने हेतु अगले एक वर्ष का रोड मैप तैयार करके 31 मार्च तक विभाग को सौंपेंगे । इसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के मुद्दों के लिए अलग–अलग कार्य योजना तैयार की जाएगी ।

दस्तक अभियान के दौरान क्षय रोगियों की भी की जाएगी पहचान

• बुखार के मरीजों और कुपोशित बच्चों की भी तैयार की जायेगी सूची

लखनऊ,(एस.एन.लाल) – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश को वर्ष 2025 तकटीबी से मुक्त करने के संकल्प को पूराकरने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में 10 मार्च से शुरू हो रहे दस्तक अभियान के तहत घर–घर बुखार के रोगियों के साथ टीबी के मरीज भी ढूंढे जाएंगे– यह जानकारी जिला क्षय रोग अधिकारी डा. ए.के.चौधरी ने दी। उन्होंने बताया– यह पहली बार है जब आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ घर–घर जाकर बुखार के रोगियों, टीबी के रोगियों, कुपोशित बच्चों, दिमागी बुखार से दिव्यांग हुए व्यक्तियों और जन्म और मृत्युपंजीकरण से वंचित लोगों की सूची बनायेंगी।

डा. चौधरी ने बताया–देश से टीबी को वर्ष 2025 तक हम तभी समाप्त कर पायेंगे जब टीबी के रोगियों को ढूंढ पायें और उनका पूरा इलाज सुनिश्चित करापायें। अभी तक एक्टिव के सफाइंडिंग (एसीएफ) अभियान के माध्यम से हम यह काम करते थे जो साल में दोबार चलाया जाता है, यह अभियान जनपद की केवल 10 फीसद जनसँख्या को कवर करता है। दस्तक अभियान में 100 फीसद आबादी कवर होते हुए क्षय रोगी चिन्हित हो सकेंगे। यह कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । हम दृढ़ता से कह सकेंगे कि कोविड के कारण जो रोगी कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए वह सभी कार्यक्रम से जुड़ पायेंगे।

दस्तक अभियान वर्ष 2017 से चलाया जा रहा है लेकिन यह पहली बार हुआ है जब दस्तक अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर–घर जाकर टीबी के संभावित रोगियों की पहचान होगी। इस अभियान के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा टीबी के रोगियों की पहचान हो पायेगी।

सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाईजर अभय चन्द्रमित्रा ने बताया–आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर– घर जाकर लोगों से बुखार सहित टीबी के लक्षणों के बारे में पूछेंगी। संभावित रोगियों की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना एएनएम के माध्यम से ब्लाक तथा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के स्टाफ को देंगी। तत्पश्चात ऐसे लोगों की टीबी की जाँच कराई जाएगी और क्षयरोग चिन्हित होने पर उनका निःशुल्क इलाज शुरू किया जायेगा।

जिला क्षय रोग अधिकारी ने बताया–जिले में वर्ष 2017 में 13,425 , 2018 में 18,853, 2019 में 24,830 और 2020 में 17,321 क्षय रोग के मरीज थे। वर्ष 2021 में क्षय रोग के कुल 2907 मरीज खोजे गए हैं।

पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा को पवित्र मानकर उसका पालन कीजिए : आलोकमेहता

- मीडिया का काम समाज में निराशा पैदा करना नहीं है
- आईआईएमसी में 'शुक्रवार संवाद' का आयोजन

नईदिल्ली, (ऋचा द्विवेदी)'' पत्रकारिता की लक्ष्मणरेखा को पवित्र मानकर उसका पालन कीजिए। यह मार्ग कांटों भरा भले ही हो, लेकिन यदि आपके पास पूरे तथ्य और प्रमाण हैं, आपको अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी है, तो आपको बेबाक होकर अपनी बात रखनी चाहिए।" यह विचार पद्मश्री से सम्मानित वरिश्ठ पत्रकार और एडिटर्सगिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आलोक मेहता ने शुक्रवार को भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआई एमसी) द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'शुक्रवार संवाद' में व्यक्त किए। इस अवसर पर आईआईएमसी के महानिदेश कप्रो. संजय द्विवेदी विषेश तौर पर उपस्थित थे।

'पत्रकारिता की लक्ष्मणरेखा' विशय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मेहता ने कहा कि पत्रकारिता करते समय किसी के प्रति कोई दुराग्रहन हीं रखना चाहिए। मौजूदा दौर में अधिकतर लोग जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं–कहीं लोग अपनी लक्ष्मण रेखा को पार भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाता है, लेकिन भारत में अब तक हम आचार संहिता को अनिवार्य रूप से लागू करने में सफल नहीं हो पाए हैं।

Newly Introduced Intraocular Therapy for Diabetic Retinopathy

Pathologic changes of the retina caused by diabetes is the leading cause of blindness in working adults. Diabetic retinopathy has no known cure, treatment options are inadequate, and prevention strategies offer limited protection.

"We are not aware of another study that has demonstrated a therapy capable of reversing this form of retinal pathology, particularly in the presence of persistent untreated hyperglycemia," commented lead investigator Maria B. Grant, MD, of the Eugene and Marilyn Glick Eye Institute of Indiana University, Indianapolis, IN.

"This research is based on the hypothesis that an imbalance between two axes of the RAS is a key initial event that leads to development of diabetic microvascular complications," explained Dr. Grant. The two axes consist of the classic and vasoprotective RAS.

The proinflammatory, vasoconstrictive classical RAS component is normally kept in check by a vasoprotective axis that is both anti-inflammatory and vasodilatory. Angiotensin converting enzyme-2 (ACE-2) is the primary enzyme of the vasoprotective component.Administration of AAV-ACE--the therapeutic agent under evaluation--directly into the vitreous cavity of the eye using an adeno-associated virus vector, increases ACE-2 expression.

Investigators used mice, some of which were injected with streptozotocin (STZ) to induce diabetes. The protective effects of AAV-ACE2 were examined by performing two sets of experiments. In one cohort, AAV-ACE2 was administered two weeks prior to STZ injection. In a second cohort, to evaluate whether the enhanced expression of ACE2 could reverse diabetic retinopathy, AAV-ACE2 was administered six months after STZ, when diabetes and retinopathy were already established.

The investigators found that both strategies effectively decreased the numbers of proinflammatory cells present in the diabetic retina. Leukostasis--abnormal aggregation and clumping of white blood cells within blood vessels--was only seen in diabetic animals receiving control injections.

In addition, using a histological endpoint of retinal vascular degeneration, called acellular capillaries, the group determined that the AAV-ACE2 injection could reverse the diabetes-induced pathology. "These findings are very exciting because it is traditionally believed that this endpoint of vascular degeneration, acellular capillaries, represents an irreversible lesion," emphasized Dr. Grant.

One strength of this experimental approach is that intravitreal administration eliminates the problem of the blood-retinal barrier interfering with access of systemically-administered therapeutic agents. The investigators envision that inducing ACE2 overexpression to improve vascular characteristics and decrease inflammation may be translatable to other vascular diseases such as stroke, kidney disease, and heart disease.

Stada first-quarter profit beats on German generic boost

German generic drugmaker Stada reported better than expected quarterly adjusted earnings as it eked an increase in revenues from the embattled market for bulk purchase agreements with German medical insurers. The beat gives management firepower against an activist investor seeking to replace Stada's chairman and four other supervisory board members at a shareholder meeting on June 9.

Stada will likely face questions about Active Ownership's investment and speculation that the investor could force a sale or breakup of the company in conference calls later on Thursday.The speculation has driven the share price higher, but a source told Reuters earlier this month the shareholder has no plans to push for a sale. Adjusted net income was up 6 percent at 40 million euros ($46 million) in the first quarter, Stada said on Thursday, compared with average analyst expectations for 37 million euros in a Reuters poll.Stada said profits were driven by the generic drugs business in Germany, where sales rose 8 percent to 76 million euros. Stada, which also makes branded non-prescription treatments and diagnostic kits, said it was still forecasting a slight gain for 2016 in adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) and adjusted net income. Shares in Stada were up 0.8 percent at 0830 GMT, outperforming a 0.5 percent weaker MDAX.

Aetna plans to remain in Obamacare markets, may expand

Health Insurer Aetna Inc on Wednesday said it plans to continue its Obamacare health insurance business next year in the 15 states where it now participates, and may expand to a few additional states.

"We have submitted rates in all 15 states where we are participating and have no plans at this point to withdraw from any of them," said company spokesman Walt Cherniak. But he noted that a final determination would hinge on binding agreements being signed with the states in September.

Aetna sells the individual coverage on exchanges created by the Affordable Care Act, also called Obamacare. By also filing proposed rates in several other states, Aetna said it had preserved its options to participate in them as well next year. It declined to identify the potential new markets.The 15 states where it currently participates are Arizona, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kentucky, Missouri, Nebraska, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Texas and Virginia.Aetna earlier this year said its Obamacare business had operating losses of about 3 to 4 percent in 2015, with improvements seen in the latter part of the year. It is hoping the business will have a break-even performance in 2016.

Rival insurers UnitedHealth Group Inc and Anthem Inc have missed profit expectations because of losses in their own individual Obamacare businesses.UnitedHealth Group has said it will exit most of its Obamacare exchanges next year

Complete Health Care Under One Roof

KHUSHI MEDICAL CLINIC & RESEARCH CENTER

Dr. Dwivedi's

KHUSHI MEDICAL & RESEARCH CENTER

(A Multi-Speciality Medical-Health Center)

SHOP-15/107, 15/25, Ganesh Market, , Near C-Block Chauraha, Opposite Hanuman Mandir, Indira Nagar, Lucknow-226016

Phone : 9450097512 * 8090111100

E-mail: kmrc.india@gmail.com

PATHOLOGY

Dr Lal PathLabs

भारत का सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वसनीय पैथालाजी नेटवर्क

HOMEOPATHY

Khushi Homeopathic Clinic & Research Center

Lucknow's Best Homeopathic Research Center for Chronic Diseases

PHYSIOTHERAPY

Khushi Physiotheraphy Clinic & Research Center

Finest Physiotherapy Clinic with Modern Machines and Complete Rehabilitation

Homeopathic Consultation • Pathology • Physiotherapy

Homeopathic Pharmacy • Diagnostics • Health Check-ups

Abortion rates fall to historic low in wealthy countries, little changed elsewhere

Abortion rates have dropped dramatically in the past 25 years to historic lows in wealthy countries, but dipped only slightly in poorer developing nations, according to a global study published on Wednesday.

The study - by the World Health Organization (WHO) and Guttmacher Institute - also found that imposing restrictive laws does little to lower abortion rates, but is more likely to force people into having unsafe terminations.

It estimated that on average 56 million abortions took place each year worldwide from 2010 to 2014.

The overall findings highlight a lack in poorer countries of access to modern contraception methods - such as the pill, implants and coils - to reduce unwanted pregnancies, the researchers said.

"In developing countries ... family planning services do not seem to be keeping up with the increasing desire for smaller families," said Gilda Sedgh, who led the research at the Guttmacher Institute in the United States.

More than 80 percent of unintended pregnancies are in women who are not getting the contraception they need, she said, "and many unwanted pregnancies end in abortion".

She said that by contrast the downward trend in abortion rates in richer countries is largely due to "increased use of modern contraception that has given women greater control over the timing and number of children they want."

Published in The Lancet medical journal, the study used abortion data from nationally representative surveys, official statistics and other published and unpublished studies, along with information on the level of unmet need for contraception and the prevalence of contraceptive use, by type of method.

The researchers then used a statistical model to estimate levels and trends in abortion incidence for all major world regions and subregions from 1990 to 2014.

The researchers found that between 1990 and 2014, the developed world's annual abortion rate per 1,000 women of childbearing age (15–44 years) dropped from 46 to 27, mainly as a result of the rate in Eastern Europe more than halving as modern contraceptive methods became more widely available.Yet in poorer countries, the abortion rate remained virtually unchanged, dropping from 39 to 37.

The study also found that termination rates were similar in countries where abortion is legal and where it is prohibited.Where abortion is prohibited altogether, or allowed only to save a woman's life, the rate was 37 abortions per 1,000 women, compared with 34 per 1,000 where it is legal.

"More women living in countries with the most restrictive abortion laws have an unmet need for contraception - that is, they want to avoid getting pregnant but are not using a method of family planning - than women in countries with more liberal laws, and this adds to the incidence of abortion in countries with restrictive laws," Sedgh said.

EAST EUROPE

Over the last 25 years, Eastern Europe has seen the biggest drop in abortion rates, but rates also fell in Europe and North America, the study found.

The overall abortion rate in Africa, where the vast majority of abortions are illegal, remained virtually unchanged at 34 abortions per 1,000 women in 2014 versus 33 in 1990–94."We already know nearly $300 million are spent each year on treating the complications from unsafe abortions," said Bela Ganatra, a WHO scientist who also worked on the study.She said the high rates of abortion in developing countries showed the need to improve access to effective contraception. "Investing in modern contraceptive methods would be far less costly to women and society than having unwanted pregnancies and unsafe abortions," she said.

AstraZeneca drug wins orphan status in thyroid cancer

An experimental AstraZeneca drug that failed last year as a treatment for a rare cancer of the eye has been awarded special "orphan" status in the United States for a type of thyroid cancer.

The British drugmaker, which is relying on cancer treatments to revive its fortunes following a wave of patent expiries, said on Thursday the decision showed the potential importance of selumetinib for some patients.Orphan status is awarded to medicines promising significant benefit in treating rare, life-threatening diseases and the designation provides companies with special development and market exclusivity incentives.

AstraZeneca's drug is being tested for patients with advanced differentiated thyroid cancer who fail to respond adequately to radioactive iodine.

Selumetinib, which belongs to a class of cancer drugs known as MEK inhibitors, failed to meet its goal in a late-stage trial for uveal melanoma in July 2015.

The drug is also being investigated as a treatment for advanced non-small cell lung cancer. However, it is viewed by analysts as less important commercially than AstraZeneca's recently launched cancer drugs Tagrisso and Lynparza, and its experimental product durvalumab.

House passes bill to aid children born into opioid dependency

A sign marks the entrance to the Neonatal Therapeutic Unit at Cabell Huntington Hospital, where staff members have acted to treat an alarming number of drug-dependent newborns, in Huntington, West Virginia, October 19, 2015. REUTERS/ Jonathan Ernst

A sign marks the entrance to the Neonatal Therapeutic Unit at Cabell Huntington Hospital, where staff members have acted to treat an alarming number of drug-dependent newborns, in Huntington, West Virginia, October 19, 2015.

The House of Representatives on Wednesday unanimously passed legislation to improve safety planning for children who are born dependent on opioid drugs.

A similar bill is pending in the Senate. It is one of more than a dozen new measures that are aimed at addressing a U.S. epidemic of addiction to pain pills and cheap heroin. The legislation came in response to a Reuters investigation last year, titled "Helpless and Hooked," which revealed that at least 110 babies had died since 2010 after being born dependent or exposed to opioids and sent home with parents ill-prepared to care for them.

"It's hard to imagine that stories like these could be any more tragic," Rep. Lou Barletta, a Pennsylvania Republican who is the prime sponsor of the bill, said on the House floor. "Unfortunately, they are. Because they should have and in many cases could have been prevented."

Only nine of the 50 U.S. states followed a federal law requiring them to track and help those newborns, Reuters reported. The news agency found that more than 130,000 newborns were diagnosed with drug withdrawal over the last decade, but most of them weren't reported to state child-protection authorities.In April, the U.S. Department of Health and Human Services asked all states to report by June 30 whether and how they are following the existing law, known as the Child Abuse Prevention and Treatment Act. States receive federal funding after giving assurance they are complying.

Rep. Katherine Clark of Massachusetts, the leading Democratic co-sponsor, emphasized that the new legislation would require help for not only the newborn but also for the mother and family. That provision is aimed at overcoming resistance to reporting cases of newborn addiction among doctors and other healthcare workers, who sometimes fear that mothers may be punished if the cases come to official attention. "This important step with this bill is to ensure that the whole family is healthy and successful and supported," Clark said. The measure, formally known the Improving Safe Care for the Prevention of Infant Abuse and Neglect Act, passed 421-0.Children's advocates are seeking more federal funding to go with the commitment. "We would view this as a good first step, but they need to make it real and put some money in it," said John Sciamanna, vice president of public policy for the Child Welfare League of America.

Among the other opioid-related bills adopted by the House on Wednesday was one designed to help states emulate a pilot program for drug-affected newborns in Huntington, West Virginia. Rep. Evan Jenkins, a Republican who helped create the Huntington facility, known as Lily's Place, before he became a congressman, said his bill would help improve access to care for poor babies and women on Medicare.

Studies of pregnant mice with Zika cement microcephaly link

An edes aegypti mosquito is seen inside a test tube as part of a research on preventing the spread of the Zika virus and other mosquito-borne diseases at a control and prevention center in Guadalupe, neighbouring Monterrey, Mexico, March 8, 2016.Studies from three different teams of scientists offered proof on Wednesday that Zika can reach and destroy brain cells in the fetuses of pregnant mice, findings that solidify the link between the mosquito-borne virus and birth defects.

Prostate Cancer Test Identifies Molecular Changes in PSA Protein Accurately

The Cleveland Clinic research was presented at the American Urological Association annual meeting. The study - part of an ongoing multicenter prospective clinical trial - found that the IsoPSATM test can also differentiate between high-risk and low-risk disease, as well as benign conditions.

'IsoPSATM test can identify molecular changes in prostate specific antigen (PSA) protein more precisely and also differentiate between high-risk and low-risk disease. '

Although widely used, the current PSA test relies on detection strategies that have poor specificity for cancer - just 25 percent of men who have a prostate biopsy due to an elevated PSA level actually have prostate cancer, according to the National Cancer Institute - and an inability to determine the aggressiveness of the disease.

The IsoPSA test, however, identifies prostate cancer in a new way. Developed by Cleveland Clinic, in collaboration with Cleveland Diagnostics, Inc., IsoPSA identifies the molecular structural changes in protein biomarkers. It is able to detect cancer by identifying these structural changes, as opposed to current tests that simply measure the protein's concentration in a patient's blood.

"While the PSA test has undoubtedly been one of the most successful biomarkers in history, its limitations are well known. Even currently available prostate cancer diagnostic tests rely on biomarkers that can be affected by physiological factors unrelated to cancer," said Eric Klein, chair of Cleveland Clinic's Glickman Urological & Kidney Institute. "These study results show that using structural changes in PSA protein to detect cancer is more effective and can help prevent unneeded biopsies in low-risk patients."

The clinical trial involves six healthcare institutions and 132 patients, to date. It examined the ability of IsoPSA to distinguish patients with and without biopsy-confirmed evidence of cancer. It also evaluated the test's precision in differentiating patients with high-grade (Gleason =7) cancer from those with low-grade (Gleason = 6) disease and benign findings after standard ultrasound-guided biopsy of the prostate.

Substituting the IsoPSA structure-based composite index for the standard PSA resulted in improvement in diagnostic accuracy. Compared with serum PSA testing, IsoPSA performed better in both sensitivity and specificity.

"We took an 'out of the box' approach that has shown success in detecting prostate cancer but also has the potential to address other clinically important questions such as clinical surveillance of patients after treatment," said Mark Stovsky, staff member, Cleveland Clinic Glickman Urological & Kidney Institute's Department of Urology. Stovsky has a leadership position (Chief Medical Officer) and investment interest in Cleveland Diagnostics, Inc.

"In general, the clinical utility of prostate cancer early detection and screening tests is often limited by the fact that biomarker concentrations may be affected by physiological processes unrelated to cancer, such as inflammation, as well as the relative lack of specificity of these biomarkers to the cancer phenotype. In contrast, clinical research data suggests that the IsoPSA assay can interrogate the entire PSA isoform distribution as a single stand-alone diagnostic tool which can reliably identify structural changes in the PSA protein that correlate with the presence or absence and aggressiveness of prostate cancer."

Regular Exercise can Reduce the Risk of Cervical Cancer

"To our knowledge, this is the first U.S.-based study looking at the associations between physical inactivity and cervical cancer. Our findings suggest that abstinence from regular physical activity is associated with increased odds of cervical cancer," says J. Brian Szender, MD, MPH, lead author of the study and a fellow in the Department of Gynecologic Oncology at Roswell Park.

'Women who did not engage in any physical activity were two-and-a-half times more likely to develop cervical cancer when compared to women who reported that they exercise.'

The study included 128 patients diagnosed with cervical cancer and 512 women suspected of having cancer but ultimately not diagnosed with the disease. Physical inactivity was defined as having engaged in fewer than four sessions of physical activity per month. The reported rates of physical inactivity were 31.1% for women diagnosed with cervical cancer and 26.1% among the control group.

The difference in risk remained present even after accounting for potential differences in smoking, alcohol intake, family history of cervical cancer and body mass index. The findings show that women who reported that they did not engage in any physical activity were two-and-a-half times more likely to develop cervical cancer when compared to women who reported that they exercise.

"We think that this study sends a powerful public health message: that a complete lack of exercise is associated with the greater likelihood of developing a serious disease. Our findings show that any amount of exercise can reduce cervical cancer risk," says Kirsten Moysich, PhD, MS, senior author of the study and Distinguished Professor of Oncology in the Department of Cancer Prevention and Control at RPCI. "In addition to smoking cessation and undergoing regular screening, we have identified another important modifiable risk factor for this disease."

With Best Compliments from :

NIDHISH MEDICALS

S-15/10, Ganesh Market, Indiranagar, Lucknow.

Ph.:9415797272

SHIVA MEDICALS

We stock & Sale Quality Medicine

S-15/8, Ganesh Market
Near Hanuman Mandir
Indiara Nagar,
Lucknow - 226 016

Cell : 9935832385

KHUSHI FOUNDATION

For any Health need call AYUSH Helpline Number

8765295384

Mor. 10:00 am - Eve. 7:00 pm

write to us : dryesno@gmail.com

visit us : www.khushiclinic.com, www.khushifoundation.net

HEALTH PARTNER : KHUSHI CLINIC AND WELNESS CENTER

• HOMEOPATHY • AYURVEDA • UNANI • YOGA

Sadbhawana Hospital

Sarvoday Nagar, Lucknow.

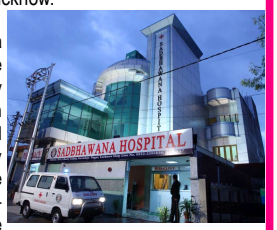

"Multispecialty" Sadbhawana Hospital is a landmark tertiary care health destination managed by highly experienced group. First of its kind in Lucknow, the 50+ bedded hospital has the state-of-the-art technology over virtually all specialties. The technology advantage is complemented by the man power excellence providing sophisticated and specialized medical care at affordable cost. With a team dedicated in bringing you a world of care with every visit. "World-class medical care, friendly, devoted service and affordability are the key features in our every touch."

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक अम्बरीश द्विवेदी द्वारा यज़्दा ए काम्यूनीकेशन ग्रुप, ३३६ प्रिन्स काम्प्लेक्स, हज़रतगंज, लखनऊ से मुद्रित एवं सी-६६५, इन्दिरा नगर, लखनऊ से प्रकाशित किया। RNI No.: UPBIL/2012/46720

सम्पादक : *अम्बरीश द्विवेदी* कार्यकारी सम्पादक : एस.एन.लाल सम्पादकीय सलाहकार : मनोज तिवारी प्रबन्धक : एस.पी.द्विवेदी

सम्पर्क : 9450097512, 0522-4001081, 9307282052, e-mail: khushisamay.india@gmail.com , शाखा कार्यालय : 338, तृतीय तल, प्रिन्स काम्प्लेक्स, हज़रतगंज, लखनऊ, रामाज्ञा, गोईन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ